दैनिक जागरण

संकल्प आत्मबल से ही पूरे होते हैं

प्रधानमंत्री का संदेश

नव वर्ष के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साक्षात्कार में करीब-करीब सभी ज्वलंत मुद्दों पर जिस विस्तार से जवाब दिए उससे आने वाले दिनों का राजनीतिक एजेंडा तय हो सकता है। इसी साक्षात्कार में उन्होंने अपनी सरकार की ओर से किए गए कार्यों का मूल्यांकन जिस तरह जनता पर छोड़ा उससे यह स्पष्ट हुआ कि उन्हें अपनी उपलब्धियों पर संतोष है और वह आम चुनावों का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था, राजनीति, रक्षा-सुरक्षा और सामाजिक मसलों से लेकर अन्य अनेक मुद्दों से संबंधित सवालों के जो जवाब दिए उन पर विपक्ष की असहमति और अलग राय हो सकती है, लेकिन बेहतर होगा कि वह यह समझे कि अयोध्या विवाद का शीघ्र समाधान सबके हित में है और इसे राजनीति का विषय बनाने से बचा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए फिलहाल अध्यादेश नहीं लाया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की कोई पहल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हो सकती है। यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने एक तरह से वह मांग खारिज कर दी जिसके तहत अयोध्या विवाद के समाधान के लिए कानून बनाने या फिर अध्यादेश लाने को कहा जा रहा है। मौजूदा हालात में यह ठीक भी है, क्योंकि जो मसला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हो उस पर कानून बनाने या फिर अध्यादेश लाने का औचित्य नहीं बनता। इसलिए और भी नहीं बनता, क्योंकि अयोध्या विवाद के हल के लिए लाया जाने वाला कोई भी कानून न्यायपालिका के समक्ष ही पहुंचेगा। इस तरह मामला वहीं का वहीं रहेगा।

अयोध्या मसले पर प्रधानमंत्री का बयान एक ऐसे समय आया जब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर से शुरू होने वाली है। यह मसला सतह पर आया ही इसलिए, क्योंकि बीते साल के अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई टाल दी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मांग तेज ही नहीं होती। जो भी हो, कम से कम अब यही अपेक्षित है और आवश्यक भी कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले का निपटारा शीघ्र करे। इससे भी अच्छा यह होगा कि इस मसले का समाधान आपसी बातचीत के जरिये निकालने की कोशिश की जाए। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि भारतीय समाज को प्रभावित करने वाले इस मसले का हल आपसी सहमति से निकले। इससे देश में न केवल शांति एवं सद्भाव का वातावरण बनेगा, बल्कि दुनिया को एक अच्छा संदेश जाएगा। अयोध्या विवाद को आपसी सहमति से समाधान एक सुनहरा अवसर है। इसका उपयोग किया जाना चाहिए। यह सही है कि अतीत में आपसी बातचीत के जरिये अयोध्या विवाद का समाधान निकालने की कोशिश सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि नए सिरे से कोई पहल न की जाए। अगर राजनीतिक संकीर्णता और स्वार्थ को परे रखा जा सके और सामाजिक सद्भाव की महत्ता को समझा जा सके तो इस जटिल विवाद का समाधान बहुत आसानी से निकल सकता है। बेहतर होगा कि वे लोग आएं जो अयोध्या विवाद के समाधान के साथ सद्भाव के भी हामी हैं।

साइबर अपराध पर रोक

झारखंड में विकास की रफ्तार समय के साथ तेज होती जा रही है। जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। वहीं झारखंड के साइबर अपराधियों की चर्चा भी पूरे देश में है। दो दिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया और उनके मैसेंजर से लोगों से एटीएम के डिटेल मांगे गए। स्पीकर ने तत्काल लोगों से ऐसे किसी भी ब्योरे को साझा न करने की अपील की। पिछले कुछ वर्षों में झारखंड में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। लोगों की गाढ़ी कमाई सेकेंड में उड़ा लेने वाले साइबर अपराधियों की नजर हाईप्रोफाइल लोगों पर भी है। वे उनके सोशल साइट्स का इस्तेमाल हेराफेरी करने के लिए हैक कर रहे हैं। सरकारी वेबसाइट पर भी हैकर्स ने कई दफा कब्जा जमाया है। राज्य का जामताड़ा जिला साइबर अपराधियों के लिए कुख्यात है। बंगाल से सटे इस जिले में अक्सर राज्य पुलिस के साथ-साथ अन्य प्रदेशों की पुलिस दबिश देती है और यहां से साइबर अपराधियों को पकड़कर ले जाती है। यहां से पकड़े जाने वाले अपराधी कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वे इतने शातिर होते हैं कि झटके में लोगों को ठग लाखों रुपये एकाउंट से गायब कर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत कर रही है। जिसकी वजह से ये पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद लगातार वारदातें जारी है। वर्तमान में रांची में एक राज्यस्तरीय साइबर थाना है, जबकि रांची जिला का अपना कोई साइबर थाना नहीं है। अन्य छह साइबर थाने छह विभिन्न जिलों में संचालित हैं। पुलिस प्रशासन अब तीन और जिलों रांची, हजारीबाग और बोकारो जिले में साइबर थाना खोलने जा रही है। जिलों में साइबर थाना खुलने से वहां दर्ज होने वाले दो लाख रुपये तक के ठगी के मामले उसी जिले के साइबर थाने के जांच के अधीन होंगे। उक्त थाने में साइबर विशेषज्ञ रखे जाएंगे, जिन्हें राज्यस्तरीय साइबर थाने का तकनीकी सहयोग भी मिलेगा। इन थानों के सक्रिय रूप से काम करने के बाद साइबर अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। जिससे इन अपराधियों पर नकेल कसी जा सके।

नए साल में नई सोच की दरकार

प्रदीप सिंह

अभी आम चुनाव के बारे में कुछ कहना कठिन है, लेकिन यह यकीन के साथ कहा जा सकता है कि नए साल में भाजपा को विमर्श बदलने की सख्त जरूरत है

चुनावी साल होने के नाते नए साल में राजनीतिक मोर्चे पर काफी कुछ बदलाव अपेक्षित है। बदलाव की अपेक्षा इसलिए भी है, क्योंकि चुनौती भजापा के समक्ष भी है और कांग्रेस के समक्ष भी। इस अपेक्षा के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसकों की मानें तो सब कुछ ठीक है और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव नतीजों से कुछ खास नहीं बदला है और कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। जो राहुल गांधी के मुरीद हैं उनकी सुनें तो लगेगा कि सब बदल गया है और भाजपा बस जाने को है, बल्कि गई समझिए और राहुल गांधी की ताजपोशी का समय आ रहा है। जाहिर है दोनों बातें सच नहीं हो सकतीं। तो फिर सच क्या है? सचाई इन दोनों के बीच कहीं है।

राहुल गांधी के लिए दिल्ली अभी इतनी भी पास नहीं है। लोगों का भरोसा अभी राहुल पर जमा नहीं है और मोदी अभी लोगों के दिल से उतरे नहीं हैं, परंतु शिकायतें तो हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार गंवाने का 2019 के लोकसभा चुनाव की संभावनाओं पर कितना असर पड़ेगा, इस बारे में यकीन के साथ कुछ भी कहना कठिन है। एक बात जरूर यकीन के साथ कही जा सकती है कि भाजपा को विमर्श बदलने की सख्त जरूरत है। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ही देश का एजेंडा सेट कर रहे थे। पिछले छह महीने या कहें कि गुजरात और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद से विमर्श बदलने लगा है। कांग्रेस दोनों प्रांतों में हार गई, परंतु माहौल ऐसा बना मानो भाजपा की हार और कांग्रेस की जीत हुई है। बात सिर्फ इतनी नहीं कि राहुल गांधी को लोगों ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है।

हाल के विधानसभा चुनावों पर गौर करें तो कांग्रेस की तस्वीर वैसी नहीं जैसा विमर्श बन रहा है। मिजोरम में दस साल बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर ही नहीं हुई, बुरी तरह हारी। वैसे ही जैसे छत्तीसगढ़ में भाजपा हारी। तेलंगाना जहां 2014 के चुनाव के समय कांग्रेस सत्ता में थी, उसका सूपड़ा साफ हो गया। पांच साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी तेलंगाना का मतदाता कांग्रेस की ओर देखने को तैयार नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में 15 साल की सत्ता विरोधी हवा के बावजूद कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, बल्कि भाजपा से कम वोट मिले। राजस्थान में भी दोनों दलों के बीच एक फीसदी वोट का अंतर है। इन तथ्यों के बावजूद विमर्श यह बन रहा है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है।

सच यह है कि ब्रैंड मोदी को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। बस उसमें एक ठहराव, थकावट सी आ गई है। जरूरत है इस ब्रैंड के पुनर्युवीकरण की। लोग सातत्य के साथ बदलाव भी चाहते हैं। मनुष्य की नएपन की चाह में कभी ठहराव नहीं आता। यह चाहत निरंतर और सनातन है। मोदी को अपने भाषणों और कथ्य में नएपन की जरूरत है। किसी भी वक्ता और खासतौर से जब वह राजनेता हो तो प्रेडिक्टेबल होना अच्छा नहीं होता। उससे नीरसता आती है। यह बात जब पार्टी के लोग भी महसूस करने लगें

अवधेश राजपूत

तो इसका मतलब है कि कुछ नया करने का वक्त आ गया है। मोदी को अब कुछ नई बातें नए ढंग से लोगों के सामने रखने की जरूरत है।

भाजपा के रणनीतिकारों को यह भी समझना चाहिए कि आक्रामक होने और नकारात्मक होने में फर्क है। नकारात्मकता और आक्रामकता एक सीमा के बाद नुकसान करने लगती हैं। दूसरी बात, अतीत पर एक सीमा से ज्यादा निर्भरता के फायदे समय के साथ तेजी से घटने लगते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पिछले कुछ दिनों के बयान, बिहार में सीटों के बंटवारे में जो हुआ और दूसरे सहयोगी दलों का रुख, इसका संकेत है कि भाजपा में 160-क्लब फिर से सक्रिय हो गया है। इस बार इस क्लब की अगुआई नितिन गडकरी करते दिख रहे हैं। यह दीगर बात है कि इस क्लब की उम्मीदें 2014 की ही तरह अल्पजीवी होंगी। यह बात आज की परिस्थिति के आधार पर तो कही ही जा सकती है, क्योंकि भाजपा और मोदी से असंतोष, नाराजगी के बावजूद लोग मोदी को एक और मौका देना चाहते हैं। यही जनभावना पार्टी और प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

भाजपा एक और समस्या का सामना कर रही है और उसे इसका बहुत जल्दी कोई समाधान निकालना पड़ेगा। मोदी ने पिछले साढ़े चार साल में भाजपा का सामाजिक जनाधार बदल दिया है। एक समय जिस पार्टी को ब्राह्मण, बनिया और शहरी मध्यवर्ग की पार्टी माना जाता था वह अब समाज के सबसे गरीब तबके की पार्टी बन गई है। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों और पार्टी संगठन की इसमें बड़ी भूमिका है, पर दिक्कत यह है कि पार्टी अपने नए और पुराने जनाधार में सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में शहरी वोटर और व्यापारी समुदाय की नाराजगी/उदासीनता उसकी हार का सबब बनी। पार्टी को जल्द से जल्द इस संतुलन को साधना होगा।

साढ़े चार साल के मोदी राज में भ्रष्टाचार, महंगाई और नीतिगत लकवे जैसे मुद्दे मतदाता की नजर में मुद्दे ही नहीं रह गए हैं। राफेल के मुद्दे का वही हश्र होने वाला है जो 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी के मनमोहन सिंह को सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताने का हुआ था। भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों के विमर्श से बाहर चले जाने से किसानों और बेरोजगारी की समस्या राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आ गई है।

किसानों की समस्या चाहे जितनी पुरानी हो, यदि मोदी सरकार ने दबाव में आकर कर्ज माफी जैसी मांग को माना तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए इससे ज्यादा घातक कुछ नहीं होगा। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि किसानों को मदद की जरूरत है। उनकी हर संभव मदद होनी भी चाहिए, पर कर्ज माफी इस मर्ज की दवा नहीं है। इस मुद्दे को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इतना खींच दिया है कि अब दूसरे वर्गों के लोग किसानों के खिलाफ बोलने लगे हैं। वे भी अपने लिए कर्ज की माफी की मांग करने लगे हैं। यह गैर जिम्मेदाराना राजनीति राहुल गांधी और कांग्रेस के गले की हड्डी बनने वाली है।

तीन राज्यों में जीत के बावजूद राहुल गांधी के पास कर्ज माफी और मुफ्त-मुफ्त की पुकार लगाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा और मोदी से नाराज मतदाता के लिए भी राहुल गांधी को विकल्प के रूप में चुनना बहुत कठिन होगा। पांच साल बाद मतदाता 2014 के मोदी से 2019 के मोदी में कुछ अलग देखना चाहता है। कंप्यूटर की भाषा में कहें तो नए साल में देश को मोदी वर्जन टू चाहिए। जिसकी पिछली खूबियां तो हों पर कुछ नया भी हो। समय कम है, लेकिन काम मुश्किल नहीं है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

भले-बुरे का भेद मिटाती राजनीति

राजीव सचान

राजनीति और खराब राजनीति के बीच का बचा-खुचा भेद तेजी से खत्म होना चिंता का विषय बनना चाहिए

जैसे नेकी और बदी में भेद है वैसे ही आचरण और दुराचरण में, लेकिन राजनीति और खराब राजनीति में कोई अंतर नहीं और यही राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी है। इससे भी बड़ी त्रासदी यह है कि राजनीति और खराब राजनीति के बीच का बचा-खुचा भेद भी तेजी से खत्म होता जा रहा है। राजनीतिक दल एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए न केवल तथ्यों से परे बातों, बल्कि झूठी खबरों का भी सहारा ले रहे हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है, क्योंकि राजनीति में सक्रिय लोग इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा? इसी का नतीजा है कि राजनीति करने वाले अथवा राजनीति में सक्रिय लोग कितना भी बुरा व्यवहार करें उसे राजनीति ही कहा जाता है और इसी कारण अपने देश में झूठ, छल, कपट और हर तरह की शरारत भी राजनीति ही है। नेताओं के छल-कपट भरे आचरण को मुश्किल से ही क्षुद्र राजनीति की संज्ञा दी जाती है। अगर राजनीति के नाम पर यह सब कुछ होगा तो फिर वह समाज और देश का भला तो दूर रहा, अपना भी भला नहीं कर सकेगी। हालांकि किताबी तौर पर उस व्यवस्था को राजनीति के नाम से जाना जाता है जो समाज और देश को दिशा देती है, लेकिन राजनीति को परिभाषित करने वालों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर दृष्टि से खराब आचरण को राजनीति का नाम दे दिया जाएगा। आज ऐसी ही स्थिति है। अच्छा का उलट खराब होता है, लेकिन पता नहीं क्यों राजनीतिक तौर-तरीकों के विपरीत कार्य भी राजनीति ही कहलाते हैं। बिना किसी शर्म-संकोच नेतागण एक-दूसरे के दावों को झूठा बताते हैं और जब कोई सवाल खड़ा करता है तो यह कहा जाता है कि सच का पता लगाना तो मीडिया का काम है। इसका सीधा मतलब है कि नेताओं को झूठ बोलने में कोई संकोच नहीं रह गया है। आखिर मीडिया या फिर अन्य कोई झूठ फैलाते नेताओं की गलतबयानी की तहकीकात क्यों करे? यह बात और है कि कुछ लोग यह काम करने भी लगे हैं। तथ्य जांचने या फिर झूठी खबरों की छानबीन करने का काम चल निकला है तो इसके लिए राजनीतिक दल और उनके समर्थक ही जिम्मेदार हैं।

पहले राजनीति के नाम पर ओछे काम आम तौर पर छुटभैय्ये नेता या उनके समर्थक करते थे, लेकिन अब तो बड़े से बड़े नेता भी राजनीति के नाम पर कुछ भी करने या फिर कहने के लिए तैयार रहते हैं। पहले अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति अभद्र और अशालीन भाषा का इस्तेमाल आम तौर पर छोटे नेता और कार्यकर्ता करते थे, लेकिन बीते कुछ समय से यही काम बड़े नेता भी करने लगे हैं।

नतीजा यह है कि राजनीति कहीं अधिक कटुता और कलह भरी दिखने लगी है। नए साल के आगमन के बाद भी राजनीति के तौर-तरीकों में कहीं कोई बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आम चुनाव और नजदीक आ गए हैं और यह कोई नई-अनोखी बात नहीं कि चुनावी माहौल में नेताओं की जुबान कहीं अधिक बेलगाम हो जाती है। वे अभद्र और अशालीन भाषा का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करते। चुनाव जीतने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं।

आखिर यह किससे छिपा है कि हाल में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किस तरह घूम-घूम कर प्रधानमंत्री को चोर कहने का काम किया। केवल उनके भाषण ही नहीं, उनके कई ट्वीट भी किसी ट्रोल सरीखे नजर आए। राफेल सौदे को सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट मिलने के बाद भी उन्होंने प्रधानमंत्री को चोर कहना जारी रखा। उनकी ओर से भाषा की मर्यादा का जैसा उल्लंघन देखने को मिला वैसा ही उल्लंघन उनके विरोधियों ने उन्हें जवाब देने के क्रम में किया। इस पर हैरानी नहीं, क्योंकि जब एक बार किसी एक पक्ष की ओर से भाषा की मर्यादा का उल्लंघन होता है तो फिर जवाब में दूसरे पक्ष की ओर से भी ऐसा ही उल्लंघन किया जाता है। वर्तमान में जैसा राजनीतिक माहौल बन रहा है उसे देखते हुए देश को आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के क्रम में भाषा की मर्यादा का और अधिक उल्लंघन देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। समस्या केवल यह नहीं है कि राजनीतिक विमर्श और व्यवहार अमर्यादित हो रहा है। इससे भी गंभीर समस्या यह है कि संसदीय कामकाज का स्तर भी बुरी तरह गिर रहा है।

कुछ समय पहले तक तो संसद और विधानसभाओं के कामकाज में कुछ भेद दिखता भी था, लेकिन अब वह भेद भी मिटता दिख रहा है। संसद के मौजूदा सत्र को ही लें। 20 कार्यदिवसों वाले इस सत्र में मुश्किल से दो-तीन दिन ही कुछ कामकाज हुआ है। हो सकता है कि हंगामा मचाने वाले राजनीतिक दलों को सदन की कार्यवाही बाधित करने पर कुछ हासिल कर लेने का संतोष होता हो, लेकिन उनके आचरण से संसद की साख और उसकी महत्ता तेजी से खत्म होती जा रही है। अब अगर संसद नहीं चलती तो कोई उसकी अधिक परवाह करता नहीं दिखता। संसद न चलना अब एक बड़ी हद तक अपेक्षित सा हो गया है। हैरानी तो तब होती है जब किसी दिन संसद बिना स्थगन और हंगामे के चल जाती है। दरअसल जैसे यह एक मुहावरा भर रह गया है कि राजनीति देश को दिशा दिखाती है वैसे ही यह भी कि संसद देश की आकांक्षाओं का सर्वोच्च मंच है। चूंकि अब जिन मसलों पर संसद में बहस होनी चाहिए उन पर संसद से बाहर कहीं अधिक बहस हो जाती है इसलिए संसद चलने को लेकर आम लोगों की दिलचस्पी कहीं अधिक घट गई है। यह स्थिति राजनीति और लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं।

विडंबना यह है कि राजनीतिक दल इसका अहसास करते नहीं दिख रहे हैं कि संसद की महत्ता और उसकी गरिमा कम होती जा रही है। संसदीय कामकाज में कितनी गिरावट आई है, इसका एक बड़ा उदाहरण यह है कि लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा का प्रदर्शन कहीं अधिक दयनीय दिखने लगा है। अगर संविधान निर्माताओं को यह पता होता कि संसदीय कामकाज के मामले में राज्यसभा में लोकसभा से ज्यादा हंगामा होगा तो वे उसे उच्च सदन या फिर वरिष्ठों के सदन की संज्ञा हर्गिज नहीं देते। संसद के कामकाज का विधानसभाओं पर कैसा बुरा असर पड़ रहा है, इसका एक उदाहरण तब देखने को मिला जब यह खबर आई कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र केवल एक दिन का होगा।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

गलती

अपनी गलती स्वीकार करने वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं। जिनमें गलती स्वीकारने के साथ ही दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व का भाव होता है, उन्हें दूसरे आसानी से अपना नेता स्वीकार कर लेते हैं। इंसान गलतियां करता है, लेकिन उससे यह आशा की जाती है कि वह अपनी गलतियों से सबक ले। दुख की बात यह है कि हममें से अधिकांश लोग अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते। इसीलिए हमारी जिंदगी पुराने ढर्रे पर ही चलती रहती है। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो गलतियां न करता हो। इसलिए गलती करना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, बल्कि गलती से सबक न लेना जरूर आश्चर्यजनक है। इसी कारण हम जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह जान लेना भी बहुत जरूरी है कि हमने कहां गलती की है। कई बार समय रहते हमें अपनी गलती का पता नहीं चलता है। जब हमें अपनी गलती का पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। ऐसा भी होता है कि हमें अपनी गलती का अहसास हो जाता है, लेकिन जानबूझकर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। हम अपनी गलती को दूसरों पर थोपने की पूरी कोशिश करते हैं। यह अच्छी तरह जानते हुए भी किसी और ने यह गलती नहीं की है, हम दूसरों पर गलती थोपने की एक और गलती कर बैठते हैं। गलतियों का यह चक्रव्यूह ही हमें सफलता से दूर ले जाता है। इसलिए गलती के अहसास के साथ-साथ गलती को स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी है। गलती स्वीकार न कर हम लोगों को दंभी होने का परिचय देते हैं।

जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हम अपने सब हथियार डालकर जाने-अनजाने में किए गए गलत काम को स्वयं भी गलत मान रहे हैं। इससे जहां एक ओर हमारा मानसिक दबाव कम होता है वहीं दूसरी ओर लोगों की नजरों में हम सम्मान के पात्र भी बनते हैं। जब हम दिल से अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो दोबारा वह गलती होने की आशंका भी कम हो जाती है। दरअसल हम दोबारा तभी गलती करते हैं जब हम पहली गलती के बारे में या तो सोचते नहीं हैं या फिर फौरी तौर पर सोचते हैं। तो मित्रों इस बार अपनी गलती जरूर स्वीकार कीजिए। सफलता आपका इंतजार कर रही है।

रोहित कौशिक

प्रकृति के प्रकोप के आगे बेबस मानव

ुनील तिवारी

आज मानव भले ही प्रगति कर चुका हो, प्रकृति के प्रकोप के नजर आता है

ीते दिनों इंडोनेशिया में सुनामी के प्रकोप ो तकरीबन 400 से अधिक व्यक्ति काल ं गाल में समा गए। आदिकाल से ही जो ाकृतिक आपदाएं मानवता को समय-समय ार झकझोरती आई हैं उनमें से सुनामी भी एक ै। हालांकि विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में अपार उपलब्धियों के बाद भी हमारे वैज्ञानिकों ं पास कोई ऐसी प्रणाली नहीं है जिसके माध्यम ो इसका पूर्वानुमान लगाया जा सके। अब सबसे ाड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत इस तरह की ाकृतिक आपदा का सामना कर पाने में सक्षम ै। अभी हाल ही में जारी की गई 'डिजास्टर ैनेजमेंट इन इण्डिया' नामक रिपोर्ट में बताया ाया है कि भारत का 85 प्रतिशत भाग एक या क से अधिक प्राकृतिक आपदाओं के दायरे में आता है। 40 मिलियन हेक्टेयर जमीन बाढ़ के ायरे में आती है तथा देश के कुल भू-क्षेत्र का प्रतिशत चक्रवात और 68 प्रतिशत सूखे के ायरे में आता है। पिछले कुछ दशकों में भारत में ाकृतिक आपदाओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि ुई है। इससे न केवल जीवन को भारी क्षति हो ही है, बल्कि पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण के लिए अथाह धन व्यय करना पड अनुसार देश को सकल घर प्रतिशत की हानि प्रतिवर्ष प्राक कारण उठानी पड़ती है।

अब प्रश्न यह है कि आपदाओं से जन और धन किया जाय? दरअसल आप राहत कार्य शुरू करने में कम चाहिए और यदि पहले से ही तो तैयारी पहले से ही की ज भूकंप (1993) के बाद गि ने सुझाव दिया था कि किस में एक एजेंसी का गठन किय आशंका को कम करने तथ को रोकने के लिए आवश्य पहले से होने वाली तैयारियों दे। यह बात और है कि उस स ोर्ट के 3.28 ओं के को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 26 दिसंबर, 2004 को प्रशांत महासागर में आई सुनामी ने राष्ट्रीय नेतृत्व को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कुछ विशेष करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। इस दिशा में पहला प्रयास करते हुए केंद्र सरकार ने 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है, किंतु आपदा प्रबंधन की मूलभूत कमियों को दूर नहीं किया गया।

किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए थ नागरिकों का भी ता है। अतः आपदा आधारभूत तत्वों की जानकारी राष्ट्र येक नागरिक को होनी चाहिए, विशेषकर वर्ग को, क्योंकि आपदाओं के आने पर ी श्रेष्ठ स्वयंसेवक बन कर सरकारी और कारी आपदा राहत संस्थानों के साथ और बचाव कार्य को कर सकते हैं। कुल कर अपनी आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारियों बनाना होगा। कागजी घोड़ों पर सवार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की ाषा अव्यावहारिक ही नहीं, निराधार भी है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

दक्षिण एशिया भी होगा प्रभावित

सैयद अता हसनैन ने पश्चिम-दक्षिणी एशिया में बदलते हालात शीर्षक से लिखे अपने आलेख में जिन विषम हालातों का जिक्र किया है, उनमें दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों का प्रभावित होना भी लाजमी है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति अपने किए हुए वादों को अमलीजामा पहना रहे हैं वहीं दूसरी तरफ समूचे दक्षिण एशिया में खलबली मची हुई। केवल अफगानिस्तान से लगभग सात हजार अमेरिकी सुरक्षाकर्मियों की वापसी भविष्य के लिए कई सवाल खड़े करती है। अब अल कायदा और तालिबान जैसे आतंकी संगठन न केवल अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करेंगे, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इनकी जद में होंगे। वहीं भारत को भी नए सिरे से अपनी सामरिक नीतियों पर मंथन करना होगा। अब पाकिस्तान के दुर्दांत आतंकी संगठनों के भी हौसले बुलंद हो जाएंगे। अभी तक तो अमेरिकी सैनिकों के कारण उनकी नकेल कसी हुई थी। तुर्की, सीरिया, ईरान, रूस तथा अफगानिस्तान के साथ-साथ अब भारत के लिए भी अस्थिरता बढ़ सकती है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी से अब आतंकी हाल ही में बांग्लादेश में चुनी गई शेख हसीना की सरकार को भी प्रभावित करने का दुस्साहस करेंगे।

राजकुमार हंस, पलवल

निराशाजनक प्रदर्शन

नीति आयोग ने देश के पिछड़े जिलों की ताजा रैंकिंग जारी की के अनुसार तमिलनाडु के विरुधनगर, ओडिशा र उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर ने विकास के ोषजनक प्रर्दशन किया है। लेकिन कुछ राज्य को विकसित करने की योजना का लाभ उठाने में तत्पर नहीं दिख रहे हैं। आज जब संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करने की चुनौती है तब यह अनिवार्य है कि देश के विकास से वंचित इलाकों को विकसित करने की मुहिम शुरू की जाए। इस मामले में उत्तर भारत का प्रदर्शन निराशाजनक है।

चांद मोहम्मद, डॉ. भीमराव आंबेडकर कॉलेज (डीयू)

बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाला कदम

वर्तमान में भारत के नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त हैं। पिछले चार दशकों की अगर बात करें तो पढ़े-लिखे नौजवानों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। मशीनीकरण और ठेकेदारी ने बेरोजगारी और बढ़ा दी है। महंगाई में लोगों का जीवन यापन करना और भी कठिन हो रहा है। ऐसे में सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों व अधिकारियों को रिप्लेसमेंट देकर बेरोजगार नौजवानों पर कुठाराघात किया है। जब देश के युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं तो रिटायर्ड लोगों को रीप्लेस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता।

ममता, मोहन नगर पलवल

बच्चों में बढ़ेगी देशभक्ति की भावना

बच्चों में देश भक्ति को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार ने स्कूलों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके तहत अब बच्चों को अपनी हाजिरी के दौरान जय हिंद जय भारत बोलना होगा। विगत कुछ समय में कई छात्रों को आतंकवादी संगठनों से जुड़ते देखा गया है। इसका कारण देश भक्ति की गलत परिभाषा है। आतंकवादी धर्मों की आड़ में छात्रों को शस्त्र उठाने के लिए उकसाते हैं। लेकिन जब बचपन से ही बच्चे हाजिरी के समय जय हिंद जय भारत का नारा लगाएंगे तब उनमे देशभक्ति की भावना जरूर पैदा होगी। उन्हें अहसास होगा कि वह हिंदू या मुस्लिम होने से पहले एक भारतीय है। गुजरात सरकार का बच्चों में देश प्रेम की भावनाओं को जगाने का यह अच्छा प्रयास है।

निशांत रावत, डॉ. भीमराव आंबेडकर कॉलेज

अमेरिका की नुकसानदेह नीतियां

पश्चिम-दक्षिण एशिया में बदलते हालातों के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तेजतर्रार नीतियों के चलते नए साल के सामरिक रूप से अहम साबित होने का जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है, वह बेहद चिंताजनक है। दुनिया को फिक्र इस बात की है कि अपने दुखद हालातों से लड़ रहे पश्चिम एशियाई देशों के सिर से अपना हाथ हटा लेने वाली अमेरिका की नई नीति केवल एशिया को ही परेशान नहीं करेगी, बल्कि दुनिया के लिए भी खतरा उत्पन्न कर देने वाली साबित होगी। उसकी गलतियां सीरिया और अफगानिस्तान को अस्थिरता की ओर ही ले जा रही हैं।

पिंटू सक्सेना, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

ा. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के रा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।